

5.5.22

प्रार्थी वकील उपाक्षेपित। विप्रार्थी सं. 1 के वकील उपाक्षेपित।

विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 12-4-22 वास्ते खारिज करने मूल प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील विप्रार्थी सं. 1 की बहस है कि प्रार्थी ने गजम रामदेवपुरा तहसील कल्याणपुर के खसरा नम्बर 327/180 रकबा 43-00 बीघा भूमि की नेवमवरी के लिए आवेदन किया है, किंतु तहसीलदार पंचपदरा का आदेश दिनांक 8-12-10, जिदके जरिये उक्त खसरा संख्या 327/180 मूल खसरा नम्बर 180 से गिनत होकर सृजित हुआ था, थीमान अपर कलभर वाडमेर द्वारा अपील सं. 109/12 भूराशम 0/5 गोकलाशम में पारित आदेश दिनांक 7.9.17 के जरिये खसरा सं. 327/180 स्वतः ही मूल खसरा सं. 180 में समाहित होकर अप्रपक हो चुका है।

प्रार्थी ने उक्त तथ्य से बदालत को जंघेरे में रखकर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है, जो मध्य खर्चा खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील प्रार्थी की बहस है कि विप्रार्थी सं. 1 गलत तथ्यों का हवाला देकर प्रार्थी का विधि सम्मत प्रस्तुत आवेदन निरस्त करवाना चाहता

(नरेश सोनी)
उपसह अधिकारी
नाबोलरा



हैं। वास्तव में किली अदालत द्वारा मूल खसरा नंबर 180 का निरस्त हुआ ही नहीं, राजस्व रिकार्ड में आज भी खसरा नंबर 327/180 पृथक रूप से मौजूद है, जिसे पर पार्सी का कब्जा राहत है। परि तदनुसार पंचपट्टा द्वारा किया गया विभाजन निरस्त होला, तो उसका राजस्व रिकार्ड में भी अमल इरामद हो चुका होता। अतः रिजर्वी ख. 1 का उक्त प्रापनापत्र निरस्त कर विवादित भूमि की नेदमखरी के अदेश क्रमाये जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मन्न तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का रूप एवं माननीय अदालत द्वारा पारित क्षीलीय अदेश का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। पार्सी द्वारा जिले खसरा नंबर 327/180 की नेदमखरी हेतु अवेदन किया है, वह खसरा माननीय अपर कलक्टर वाडमेश के क्षीलीय अदेश के जरिये अपना स्वतंत्र अस्तित्व खोकर मूल खसरा नंबर 180 में समाहित हो चुका है। उक्त क्षीलीय अदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल इरामद होने अथवा नहीं होने से मूल खसरा नंबर 180 में कसरा नंबर 327/180 के विलीनीकरण पर कोई विपरीत प्रभाव

(नेरम सोनी)
उपलब्ध अधिक
कार्यालय

नहीं पड़ता है और मूल बसरा नम्बर 180 के लब्ध में तहसील पर पन्परा के विभाजन आदेश के निरस्त होने एवं बसरा नम्बर 327/180 के अस्तित्वहीन होने से उनकी सीमाओं का नेहमवरी के जरिये निर्धारण का कोई औचित्य अदालत की दृष्टि में, प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा पार्सी का पार्सपत्र तथ्यहीन एवं औचित्य विहीन होने से खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास युवाया गया।

पन्नावली डील सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(करेश मानी)
उपस्थ अधिकारी
बालोतस